श्री कलराज मिश्र

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति,
राजस्थान का उद्‌बोधन

**स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
बीकानेर का सत्रहवां दीक्षांत समारोह**

दिनांक 28 अगस्त, 2020 **समय दोपहर : 12. 00 बजे**

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित वेबिनार

स्थान : राजभवन, जयपुर

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर. पी. सिंह जी, दीक्षांत अतिथि पद्म भूषण डॉ. रामबदन सिंह जी, विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद् के सदस्य गण, विश्वविद्यालय परिवार के शैक्षणिक व अशैक्षणिक अधिकारियों, कर्मचारियों, उपस्थित अतिथिगण, उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र व छात्राओं एवं उनके अभिभावकगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, सदस्यगण, भाइयो और बहनो।

आप सभी को विश्वविद्यालय के सत्रहवें दीक्षांत समारोह की बधाई और शुभकामनाएं।

मैं सभी स्वर्ण पदक विजेताओं को उनके अथक प्रयासों व उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ। मैं उन सभी छात्र व छात्राओं को भी बधाई देता हूँ, जिनको आज यहां उपाधि से सुशोभित किया गया है व मैं आशा करता हूँ की आप सभी देश के विकास में योगदान देते हुए अपने जीवन में उन्नति की और अग्रसर होंगे।

कुलपति के प्रतिवेदन द्वारा ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय में गत वर्ष में शिक्षा, अनुसन्धान व प्रसार के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है। इसके लिए मैं, कुलपति व सभी कार्मिकों को बधाई देता हूँ और आशा है आप सभी पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस विश्वविद्यालय को उच्च मुकाम तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे।

कृषि की महत्ता हम सभी को ज्ञात है, जीवन की तीन सबसे बड़ी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान में रोटी और प्राकृतिक रेशे वाला कपड़ा, कृषि से ही आता है। हमारे देश में कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में करीब 18 प्रतिशत रह जाने का कारण यह नहीं है कि कृषि में विकास नहीं हो रहा बल्कि देश में विकास के साथ अन्य क्षेत्रों का विकास अधिक तेज़ी से हुआ है, जो एक विकासशील देश में होना अवश्यम्भावी है।

कृषि का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी हमारे देश की 58 प्रतिशत जनता कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, जो देश के विकास का महत्वपूर्ण अंग है।

कृषि से जुड़े सभी नीति निर्धारकों, वैज्ञानिकों, अध्यापकों, उद्यमियों और विद्यार्थियों पर बड़ी ज़िम्मेदारी है कि कृषि को नए आयामों पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ें और कृषक वर्ग को आय सुरक्षा प्रदान करने में अपना योगदान दें। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पर तो मरू क्षेत्र में कृषि विकास की भी ज़िम्मेदारी है क्योंकि इस क्षेत्र में अनुसन्धान, नए उद्यमों व नवाचार की अभी बहुत गुंजाइश है, इस क्षेत्र में काफी कुछ किया गया है और काफी कुछ किया जाना बाकी है। वैश्वीकरण के प्रभावों से कृषि क्षेत्र अछूता नहीं है। वैश्वीकरण का लाभ उठाने के लिए कृषि उत्पादों में गुणवत्ता एवं मूल्य संवर्धन पर अधिक काम करने की आवश्यकता है।

राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि व पशुपालन पर निर्भर है। मरू क्षेत्र में स्थित यह विश्वविद्यालय राज्य का पैतृक कृषि विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र के किसानों के लिए चना, मूंगफली, सरसों, कपास, मोठ व चारे की फसलों की उत्कृष्ट किस्में विकसित की हैं।

आज कृषि शिक्षा की ओर विद्यार्थियों का रुझान बढ़ा है। इसे देखते हुए मुझे कृषि का भविष्य, उज्ज्वल नज़र आता है।

जल संग्रहण व जल का सर्वोत्कृष्ट उपयोग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर वृहद् स्तर पर काम किया जा सकता है। मुझे यह जानकर खुशी है कि विश्वविद्यालय की प्रत्येक इकाई में सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

इस विश्वविद्यालय के क्षेत्र में मूंगफली, चना, ग्वार, खजूर, कपास आदि का काफी अच्छा उत्पादन होता है। औषधीय पौधों, आर्गेनिक उत्पादों, इंटीग्रेटेड फार्मिंग आदि क्षेत्रों में काम की अपार संभावनाएं हैं।

असिंचित भूमि उर्वरक, कीटनाशकों व अन्य रसायनों का प्रयोग कम होता है व साथ ही पशुधन की संख्या इस क्षेत्र में अधिक है। इन्हीं कारणों से यह क्षेत्र जैविक खेती के लिए उपयुक्त है। कृषि शिक्षा, शोध व प्रसार माध्यमों से इस पर और अधिक काम किया जाए, यह मानव स्वास्थ्य व जलवायु दोनों के लिए ही लाभकारी सिद्ध होगा।

बागवानी फसलों में गत वर्षों में किन्नू, खजूर, अनार, बेर, आंवला आदि का क्षेत्रफल बढ़ा है। अन्य कई फसलों जैसे चना, मूंगफली, ग्वार इत्यादि का भी उत्पादन इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। कटाई के बाद प्रबंधन व प्रसंस्करण पर शोध करने व उसे प्रचलित करने की दिशा में विश्वविद्यालय और अधिक काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

अच्छे उत्पादन के बाद भी किसान को उनकी उपज का सही दाम ना मिले तो उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। लघु व सीमान्त जोत वाले किसान कम उपज या ऋण के बोझ से ग्रस्त हैं। कृषि सूचना के अभाव में मंडी तक जा ही नहीं पाते। कृषि विपणन में सुधार लाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है।

इनमें उपज की मंडी से बाहर खरीद, ई–राष्ट्रीय कृषि बाज़ार, निजी मंडियों की तथा पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप की मंजूरी जैसे कदम प्रमुख हैं। आज के युग में जब हम वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तब यह आवश्यक है कि हमारे किसान कृषि उत्पादक संघ बना कर सहकारिता के सिद्धांत के साथ काम करें। विश्वविद्यालय इस दिशा में काम करके किसानों की बीज खरीदने से लेकर विपणन तक की सहायता कर सकते हैं।

यह क्षेत्र पहले ही काफी गर्म है और जलवायु परिवर्तन का यहाँ पर और भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। यह उचित समय है कि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझते हुए इनसे निपटने की तैयारी रखें व इस दिशा में जो भी अनुसन्धान अथवा परिवर्तन करने हैं, उनकी तैयारी करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की कोशिश करें, लेकिन विकास की रफ़्तार पर विराम न लगने दें। वैज्ञानिकों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में वैज्ञानिकों को मिलकर काम करने की ज़रुरत है।

सभी कृषि विश्वविद्यालयों को समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समन्वित तरीकों से परियाजनाओं पर काम करना चाहिए ताकि प्रदेश के समन्वित विकास की ओर बढ़ सकें।

भारत ऐसा देश हैं जहाँ नौजवानों की संख्या अधिक है। इन युवाओं की ऊर्जा व समझदारी से हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आज अनेक सरकारी योजनाएं आपके उद्यम को शुरू करवाने में सहायक हैं। आज आपके पास, आपके सपने पूरे करने व मुकाम हासिल करने के अनेक अवसर हैं। बस ज़रुरत है कि आप अच्छी कार्ययोजना बनाकर, इन अवसरों का लाभ उठाते हुए, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ें और देश की प्रगति में भी भागीदारी बनें।

मुझे आशा है कि सभी युवा, देश में कृषि क्षेत्र व किसानों की स्थिति सुधारने में महत्ती भूमिका निभाते हुए कृषि को एक लाभकारी उद्यम बनाने में सहयोग करेंगे ताकि भविष्य में कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का रुझान बढ़ सके।

कोविड–19 की महामारी ने जीवन के परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। आज संपूर्ण विश्व इस परेशानी से जूझ रहा है व सभी पूर्ण सतर्कता के साथ इस महामारी को हराने में लगे हैं। अचानक आई इस विपदा ने मानव जाति को संकट में डाल दिया है, किंतु हम सभी ने इस परेशानी का पूरे साहस से सामना किया है व हार नहीं मानी है।

आज उद्यमों के नए रूप सामने आये हैं। डिजिटल तरीकों से पढ़ाई हो रही है। छोटी व बड़ी सभी उम्र के लोगों ने इसका प्रयोग सीख कर काम करना शुरू कर दिया है। बड़े–बड़े आयोजन डिजिटल तरीकों से हो रहे हैं। कोविड महामारी के समय में भी कृषि क्षेत्र में शुरू में कुछ क्षेत्रों को नुकसान हुआ पर सरकार, उद्यमियों व कृषकों के मिले–जुले प्रयासों की वजह से अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

इस महामारी के समय जिस तरह से ग्रामीणों को, शहरों से अपने गांवों की तरफ दौड़ना पड़ा, वह अत्यंत पीड़ादायक रहा।

मैं विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों का आह्वान करता हूँ कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि ग्रामीणों को गावों में ही रोज़गार मिलें। यद्यपि सरकार द्वारा इसके लिए प्रधानमन्त्री ग्रामीण कल्याण रोज़गार योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसमें विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को गाँवों में ही व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अपने क्षेत्रों की संभावनाओं को पहचानें। लोकल को वोकल बनाने की आज आवश्यकता है, तब ही देश का संतुलित विकास और देश आत्मनिर्भर बन सकेगा।

आज के ग्रामीण क्षेत्र भी नवाचारों को अपनाने और इनका प्रयोग करने में पीछे नहीं हैं। आज किसान भी नई चीज़ों को समझना चाहता है और इनका फायदा उठाना चाहता है। वह भी आधुनिक तकनीकियों, खरीदारी, विपणन व सूचना के लिए डिजिटल तरीकों को अपना रहा है और आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

तकनीक, जहाँ अवसर व सहूलियत प्रदान करती है वहीं यह चुनौती भी है, इसलिए हमें इसके उपयोग में समझदारी व सही चुनाव करने की आवश्यकता है।

विश्व के बदलते परिदृश्य में शिक्षा नीति में भी परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करते हुए व शिक्षा को विश्व स्तर का बनाने के लिए सरकार बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय लोकाचार में निहित एक वैश्विक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली के निर्माण की परिकल्पना करती है और इसके सिद्धांतों के साथ संरेखित करती है, ताकि भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित किया जा सके।

नई शिक्षा नीति में सभी के लिए समान नियम होंगे। इसमें छठी कक्षा से ही व्यावसायिक कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिससे देश में रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को गावों में ही रोज़गार मिलेगा और हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। देश में शोध और अनुसन्धान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF (नेशनल साइंस फाउंडेशन) की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन (NRF) की स्थापना की जाएगी। NRF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है ।

26 नवंबर, 2019 को पूरे देश में 70वां संविधान दिवस मनाया गया। संविधान हमारा मार्गदर्शक है तथा संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की मूल भावना का उल्लेख है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिये हैं परन्तु संविधान के अनुच्छेद में 51 (क) में हमारे कर्तव्यों को भो बताया गया है। हम सभी की नैतिक ज़िम्मेदारी है कि हम मौलिक अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्यों को भी जानें और इनके अनुरूप ही व्यवहार करें।

आज जब हम संविधान पार्क का शिलान्यास कर रहे हैं, इसके मूल में भावना यह है कि आम जन को संविधान की जानकारी हो। विशेष तौर से विश्वविद्यालय के युवाओं को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। जिससे युवा इन बातों को अच्छी तरह समझ कर अपने व्यवहार में अमल में लाएं।

संविधान की व्यापक जानकारी के लिए समय–समय पर इस पर विचार विमर्श, गोष्ठियां, सेमिनार, पैनल डिस्कशन आदि आयोजित किए जाएं।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है की आज के नौजवान विद्यार्थी व शिक्षक इन बदलती हुई परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाते हुए इस क्षेत्र व देश की प्रगति में सहायक होंगे। एक बार पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ व सभी के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ।

धन्यवाद। जयहिन्द।